भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 997
10.02.2025 को उत्तर के लिए

जंगली सूअरों को घातक जानवर घोषित करना

997. श्री दुरई वाइको :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब राज्यों सहित देश में कृषि गतिविधियों और किसानों की आजीविका के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली सूअरों की स्थिति का विश्लेषण किया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से इन राज्यों में स्थिति को प्रबंधित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में भूमि की वहन क्षमता की जांच करने और जंगली सूअरों को वैज्ञानिक तरीके से मारने की सिफारिश करने के लिए कोई अध्ययन किया है या करने का प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार तमिलानाडु, केरल, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों को छूट प्रदान करती है और जंगली सूअरों को हानिकारक पशु घोषित करते हुए सीमित अवधि के लिए उन्हें मारने की अनुमति देती है; और
- (च) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों के उत्तर में विशिष्ट पशु को हानिकारक पशु घोषित करने के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) देश के विभिन्न भागों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जंगली सूअरों के साथ संघर्ष भी शामिल हैं। मानव-वन्यजीव संघर्षों के उपशमन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। जंगली सूअरों द्वारा किए गए हमलों की घटनाओं का ब्यौरा इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की संलग्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध जंगली सूअरों सहित वन्य पशुओं की संख्या का, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है।

(ङ) और (च) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(ख) के तहत राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या किसी प्राधिकृत अधिकारी को जान-माल के लिए खतरनाक हो चुके जंगली सूअरों सहित उक्त अधिनियम में संलग्न अनुसूची II में सूचीबद्ध किसी भी वन्य पशु का शिकार करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है।